

कांग्रेस शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करेगी

कांग्रेस शशि थरूर को “शहीद” का दर्जा नहीं देना चाहती, उनके खिलाफ कार्यवाही करके

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जून। कांग्रेस पार्टी के सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कांग्रेस कार्यसमिति (सीडब्ल्यूसी) सदस्य शशि थरूर के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की योजना नहीं बना रही है।

माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें “शहीद” नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आम धारणा यह है कि शशि थरूर पार्टी के लिए एक संपत्ति (असेट) हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करना कांग्रेस के लिए आत्मघाती कदम होगा।

सूत्रों के मुताबिक, शशि थरूर की राहुल गांधी से भेंट हुई थी, जहां कई मुद्दों पर बातचीत कर मामला सुलझा लिया गया। राहुल गांधी ने माना कि जो बीत गया, उसे भुला दिया जाना चाहिए और अब इस मुद्दे पर और कुछ कहने की जरूरत नहीं है।

लेकिन शशि थरूर लगातार नरेन्द्र मोदी के समर्थन में बयान दे रहे हैं, जिससे पार्टी के कुछ नेता नाराज़ और असहज हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की,

- कांग्रेस ने महसूस किया कि जनता में थरूर के बारे में छवि यह है कि थरूर पार्टी के लिए एक “एसेट” हैं और कांग्रेस उनके खिलाफ कार्यवाही करके बड़ी गलती करेगी।
- वैसे भी थरूर हाल ही में राहुल गांधी से मिले और अपनी तरफ से सारे शिकवे शिकायतें दूर कीं और यह निर्णय हुआ कि जो बीत गई, वो बात गई, अब इस पर आगे चर्चा नहीं होगी।
- पर, कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता, जैसे, खड़गे अभी भी थरूर से खुश नहीं हैं।
- खड़गे ने यह कहकर लीपा पोती की कि सीडब्ल्यूसी में 34 सदस्य हैं और उनमें से कईयों का अपना मत और सोच कई मुद्दों पर अलग है और यह थरूर पर भी लागू होता है।
- पर, खड़गे ने कटाक्ष भी किया, कईयों के लिए देश पहले आता है, पर, कईयों के लिए मोदी उससे भी ऊपर आते हैं। उनका इशारा थरूर की ओर था, जो मोदी की तारीफ करने में राष्ट्र प्रेम को भी पीछे छोड़ देते हैं।
- अमित शाह ने भी मोदी को सलाह दी है कि थरूर को पार्टी में न लें, क्योंकि वे दूसरे सुब्रमण्यम स्वामी साबित होंगे।

जिसमें उन्होंने भाजपा द्वारा आपातकाल की 50वाँ वर्षगांठ को उठाने की आलोचना की। हालांकि कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर बात हुई, लेकिन मीडिया का ध्यान केरल से वरिष्ठ नेता शशि थरूर पर केन्द्रित रहा और उनसे जुड़े कई सवाल पूछे गए।

खड़गे ने इस मुद्दे से बचने की

कोशिश की और कहा कि कांग्रेस कार्यसमिति में 34 सदस्य हैं और कई मुद्दों पर सभी की अलग-अलग राय हो सकती है, और यह बात थरूर पर भी लागू होती है।

उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि थरूर की अंग्रेजी बहुत अच्छी है, जबकि उनकी (खड़गे) काफ़ी खराब है,

और यह अच्छी बात है।

हालांकि खड़गे ने एक घुमावदार टिप्पणी करते हुए यह भी कहा कि कई लोगों के लिए पहले देश आता है, लेकिन कुछ के लिए मोदी पहले आते हैं।

इसे थरूर पर तंज के रूप में देखा जा रहा है, उनके द्वारा राष्ट्रीय कर्तव्य पर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

साल में दो बार सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा होंगी

नई दिल्ली, 25 जून। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की परीक्षा अगले साल से दो बार होगी। सीबीएसई की मंजूरी के बाद अब शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। सीबीएसई ने 2026 से साल में दो बार कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मानदंडों को मंजूरी दे दी है। यह जानकारी परीक्षा नियंत्रक संयम

- सीबीएसई ने 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर यह घोषणा की।

भारद्वाज ने दी है।

पहले फेज की परीक्षा फरवरी में शुरू होगी, 17 फरवरी 2026 से ये परीक्षाएं शुरू होगी और 7 मार्च तक खत्म हो जाएंगी। रिजल्ट की संभावित तारीख 20 अप्रैल 2026 तय की गई है, हालांकि रिजल्ट की तारीखों में बदलाव हो सकता है। वहीं, दूसरे फेज की परीक्षा 5 मई 2026 से शुरू होगी और 20 मई तक खत्म हो जाएगी। रिजल्ट की तारीख 30 जून 2026 है। सीबीएसई की पूरी डिटेल्स डेटशीट एग्जाम से कुछ दिन पहले जारी की जाएंगी।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

जयपुर, 25 जून। ज़िले की पाँचसो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ करीब एक माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त मनीष को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने 24 वर्षीय इस अभियुक्त पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी किसी अटवांसिया ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने नाबालिग के साथ उसकी मर्जी के बिना संबंध बनाए हैं। लेकिन यदि इसमें नाबालिग की सहमति भी होती तो भी

- जिले की पाँचसो अदालत ने आरोपी मनीष पर 1.75 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।

यह अपराध की श्रेणी में माना जाता, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने बताया पीड़िता के ताऊ ने 20 सितंबर, 2021 को सरुंड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया कि उसकी 17.5 साल की भतीजी 17 सितंबर को कोटपूतली स्थित कॉलेज गई थी, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटी। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अधिकांश अमेरिकावासी ईरान पर बमबारी से सहमत नहीं

सीएनएन-एसएसआरएस के नवीनतम सर्वे के अनुसार, अमेरिकावासी न केवल “एयर स्ट्राइक” के खिलाफ हैं, बल्कि, उन्हें इस बात पर भी शुबहा है कि उनका राष्ट्रपति युद्ध व शांति के बारे में सही निर्णय ले सकता है

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जून। एक नया सीएनएन-एसएसआरएस का एक सर्वेक्षण दिखाता है कि अधिकांश अमेरिकी न केवल ईरान पर सैन्य कार्रवाई को अस्वीकार करते हैं, बल्कि युद्ध और शांति के मामलों में राष्ट्रपति के निर्णय पर भी गहरा अविश्वास रखते हैं।

ईरान हमले को शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा था। लेकिन इसके बजाय, यह जन आक्रोश की लहर को जन्म दे गया। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप का ईरान पर हवाई हमले शुरू करने का फैसला खाड़ी क्षेत्र में आसमान को तो रोशन कर गया, लेकिन अमेरिका में माहौल जश्न का

- 58 प्रतिशत अमेरिकावासी यह भी मानते हैं कि एयर स्ट्राइक से ईरान, अमेरिका के लिए ज्यादा बड़ा खतरा हो गया है।
- 32 प्रतिशत अमेरिकी यह भी मानते हैं कि अमेरिका ने गंभीर कूटनीतिक प्रयास किये थे, एयर स्ट्राइक को अंजाम देने से पहले।
- इन सबका नतीजा यह है कि अमेरिकी जनता ने यह माँग की, राष्ट्रपति के युद्ध के निर्णय व कमिटेमेंट के ऊपर “चैक” (नियंत्रण) होना चाहिए तथा ट्रंप को अमेरिका की कांग्रेस से इजाजत लेने की आवश्यकता होनी चाहिए, कोई भी “मिलिटरी एक्शन” लेने से पहले। इस माँग को ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 39 प्रतिशत सदस्यों का भी समर्थन प्राप्त है।

नहीं बल्कि चिंता और विरोध का रहा। सीएनएन-एसएसआरएस के इस नए सर्वेक्षण के अनुसार, 56 प्रतिशत अमेरिकी इन हवाई हमलों का

विरोध करते हैं, और उनमें से अधिकांश तो बहुत कड़ा विरोध जता रहे हैं। ईरान पर हमले के प्रति समर्थन अपेक्षाकृत कमजोर है। यह समर्थन भी अत्यधिक

राजनीतिक रूप से विभाजित है: 82 प्रतिशत रिपब्लिकन हमलों का समर्थन करते हैं, लेकिन उनमें से भी कम से कम (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

धर्मशाला में बारिश से भारी तबाही

हिमाचल, 25 जून। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुल्लू के बाद, अब धर्मशाला में स्थिति गंभीर हो गई है। बुधवार को खिनियारा में मन्नूनी खड्ड का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके कारण इंदिरा प्रियदर्शनी जल विद्युत परियोजना में कार्यरत करीब 25 मजदूरों के बह जाने की आशंका है। अब

- इंदिरा प्रियदर्शिनी जल विद्युत परियोजना के 25 मजदूर बाढ़ में बह गए, दो के शव मिले हैं।

तक दो शव बरामद हुए हैं, लेकिन उनकी पहचान नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार, बारिश के कारण परियोजना का काम बंद था, और सभी मजदूर अस्थायी शेडों वाली मजदूर कॉलोनी में थे। अचानक मन्नूनी खड्ड और नाले का पानी कॉलोनी की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

ईरान से भारत एवं नेपाल के 300 लोगों को दिल्ली लाया गया

नयी दिल्ली, 25 जून। ‘ऑपरेशन सिंधु’ के तहत ईरान से बुधवार को भारत एवं नेपाल के 300 लोगों को दिल्ली लाया गया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर जानकारी दी कि आज शाम साढ़े चार बजे मशहद से नयी दिल्ली पहुंची एक

- ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक 3154 भारतीय नागरिकों को ईरान से भारत लाया गया है।

विशेष उड़ान से 296 भारतीय और चार नेपाली नागरिकों को ईरान से लाया गया।

प्रवक्ता के अनुसार ऑपरेशन सिंधु तहत अब तक 3154 भारतीय नागरिकों को ईरान से घर लाया जा चुका है।

केरल के नीलांबुर उपचुनाव के नतीजे ने भी थरूर के बारे में कांग्रेस की दुविधा खत्म की?

कांग्रेस ने यह सीट मार्क्सवादी पार्टी से, ग्यारह हजार मतों से जीत कर छीन ली

- यह सीट कांग्रेस ने तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर की “नाराजगी” व हिस्सेदारी नहीं होने के बावजूद जीती है।
- थरूर ने इस चुनाव में कतई भाग नहीं लिया था, क्योंकि उन्हें किसी पार्टी की रैली या आमसभा को संबोधित करने के लिए “आमंत्रित” नहीं किया गया था।
- थरूर विरोधी खेमे का कहना है, इस जीत ने थरूर के केरल में प्रभाव की पोल खोल दी।
- केरल में कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं को इस बात की खुशी है कि थरूर के पार्टी को “डैमेज पोर्टेथियल” (हानि पहुंचाने की क्षमता) को खोखला साबित कर दिया है तथा अब वे उनकी अवहेलना खुलकर कर सकते हैं।

से करीबी दिखाई हो और पार्टी के साथ अपने “वैचारिक मतभेद” को खुले तौर पर स्वीकार किया हो।

हालांकि, एक जीत से पूरे राज्य में सफलता की गारंटी नहीं मिलती। नीलांबुर में जीत का मतलब यह नहीं कि

बावजूद कांग्रेस ने यह सीट जोरदार अंदाज में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) अर्थात माकपा से छीन ली और 11,000 से अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की।

यह परिणाम कांग्रेस के लिए एक बड़ा मनोबलवर्धक संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब अगले साल राज्य में अहम विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें कांग्रेस को अपनी हार की श्रृंखला को तोड़ने और सत्ता में वापसी की उम्मीद है।

यह फैसला केरल में “थरूर प्रभाव” को लेकर चली आ रही आशंकाओं को भी शांत करता है, जिस वजह से कांग्रेस नेतृत्व अब तक उन्हें लेकर सतर्कता बरत रहा था- भले ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 25 जून। नीलांबुर उपचुनाव की जीत के साथ, अब शायद कांग्रेस शशि थरूर से जुड़ी इस विवादस्पद गाथा को पीछे छोड़ कर आगे बढ़ सकती है और आने वाले चुनौतीपूर्ण पंचायत और विधानसभा चुनावों पर ध्यान केन्द्रित कर सकती है। केरल के नीलांबुर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत ने राज्य की राजधानी से लोकसभा सांसद और हाई-प्रोफाइल असंतुष्ट नेता शशि थरूर की राजनीतिक स्थिति लगभग तय कर दी है। तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने यह कहकर प्रचार से दूरी बना ली थी कि उन्हें किसी भी रैली को संबोधित करने के लिए निमंत्रित नहीं किया गया। इसके

‘कांग्रेस ने सत्ता सुख के लिए देश में लगाया था आपातकाल’

लोकतंत्र सेनानियों ने दिखाया अदम्य साहस : मुख्यमंत्री

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार को माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह एवं संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने देश में आपातकाल की घोषणा की और भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने का घृणित प्रयास किया। ये दिन भारतीय इतिहास में संविधान हत्या दिवस के रूप में दर्ज है। उन्होंने कहा कि आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हमारा कर्तव्य है कि हम उस दौर की क्रूरता को याद करें, उससे सबक लें और संकल्प लें कि भारत का लोकतंत्र कभी फिर से इस तरह के दमन का शिकार नहीं हो। उन्होंने कहा कि आपातकाल के दौरान लोकतंत्र को कैद कर लिया गया था। नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए और प्रेस की स्वतंत्रता पर ताले लगा दिए गए। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, सुंदर सिंह भंडारी, दन्तोपन्त ऍगड़ी जैसे लोकप्रिय नेताओं को जेल में डाल दिया गया।

- ‘लोकतंत्र को किया कैद, संवैधानिक मूल्यों का किया हनन’
- मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित और पुस्तिका का विमोचन किया
- मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने डॉ. अम्बेडकर को चुनाव में टिकट ना देकर उन्हें अपमानित करने का काम किया था

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तृष्णकरण, परिव्राद व भ्रष्टाचार की राजनीति करते हुए सत्ता की लालसा में देश हित को नुकसान पहुंचाया। ये वही पार्टी है, जिसने देश के दुकड़े भी किए थे। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरूद्ध निर्णय किया, तो उन्होंने 25 जून 1975 की आधी रात को देश को आपातकाल में धकेल दिया। लेकिन भारतीय जनसंघ और राष्ट्रवादी विचारधारा के समर्थकों ने असाधारण साहस और दृढ़ता का परिचय दिया। लोकतंत्र सेनानियों ने जेल में सत्याग्रह कर आपातकाल का विरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार

ने भारत के लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। संविधान के प्रति सम्मान और डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान को याद करने के लिए मोदी जी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। साथ ही, बाबा साहब के जीवन से जुड़े पंचतीर्थ की स्थापना की गई। वहीं कांग्रेस ने डॉ. अम्बेडकर को चुनाव में टिकट ना देकर उन्हें अपमानित करने का काम किया। जब अम्बेडकर ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, तो कांग्रेस ने उन्हें हराया भी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसंघ, जिसने आपातकाल के विरूद्ध संघर्ष किया, वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में वट वृक्ष बन चुका है। आज हमारी

पार्टी में 14 करोड़ से अधिक कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। गरीब कल्याण, विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं, वहीं आतंकवाद और नक्सलवाद का खतमा हुआ है। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक निर्णय भी लिया गया। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार चार जातियों- महिला, युवा, गरीब, मजदूर के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हम पं. दीनदयाल उपाध्याय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के अंत्योदय के संकल्प को साकार कर रहे हैं।

समारोह में जयपुर सांसद मंजू शर्मा, जयपुर ग्रेटर महापौर सौम्या गुर्जर, जयपुर हेरिटेज मेयर कुसुम यादव, विधायक बालमुकुंददाचार्य और गोपाल शर्मा, जयपुर भाजपा शहर अध्यक्ष अमित गोयल सहित भाजपा प्रदेश और शहर कार्यकारिणी के पदाधिकारी, लोकतंत्र सेनानी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित भी किया और पुस्तिका का विमोचन भी किया।

जब गहलोत सरकार एक वर्ष भी पूरे नहीं कर पाई थी तभी दो खेमों में बंट गई थी : राठौड़

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने द्वीत कर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन और भ्रामक है।

राठौड़ ने कहा कि गहलोत को शावद अपने ही कार्यकाल की यादें ताजा

- राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर दिया गया बयान बेबुनियाद, तर्कहीन बताया

हो रही हैं जब उनकी सरकार एक वर्ष भी पूरे नहीं कर पाई थी कि दो खेमों में बंट गई थी। तत्समय सरकार के मंत्री-

विधायक 34 दिनों तक एक पांचसितारा होटल में कैद रहे। यहां तक की गहलोत जी ने अपने सहयोगियों को "निकम्मा

और नकारा" कहकर अपमानित भी किया।

राठौड़ ने कहा कि आज जब भाजपा सरकार जनसेवा में जुटी है तब गहलोत जी सस्ती लोकप्रियता और मीडिया की सुर्खियों में बने रहने के लिए निराधार आरोप लगाकर राजनीतिक रोटियां संक रहे हैं।

उपमुख्यमंत्री ने विद्याधर नगर के विकास कार्यों का लिया जायजा

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 14 नंबर के पास चल रहे निर्माण कार्य में जलभराव की समस्या बरकरार मिली, जिस पर स्थानीय नागरिकों की शिकायत सुन उपमुख्यमंत्री ने मौके पर ही अधिकारियों को फटकार लगाई और ठेकेदार को सख्त हद्दियात दी।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और ठेकेदारों को कल सुबह 10 बजे पुनः मौके पर तलब किया है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं पुनः स्थलीय निरीक्षण करेंगी और जलभराव की समस्या का त्वरित समाधान सुनिश्चित करेंगी।

इसके बाद उपमुख्यमंत्री मणिपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित एक नंबर क्षेत्र पहुंचीं, जहां कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया। स्थानीय लोगों ने भी कार्यों की सराहना करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया।

- लापरवाही पर लगाई फटकार,जलभराव की समस्या पर अधिकारियों और ठेकेदारों को तलब किया
- प्रभावी समाधान का दिया आश्वासन
- उपमुख्यमंत्री मणिपाल हॉस्पिटल के सामने स्थित एक नंबर क्षेत्र पहुंचीं, जहां कार्य की गुणवत्ता देखकर उन्होंने संतोष जताया

देर के बालाजी इलाके में भी उन्होंने दौरा किया, जहां पहले बारिश में कमर तक पानी भर जाता था, लेकिन इस बार बेहतर ड्रेनेज व्यवस्था के कारण पानी नहीं भर रहा। उन्होंने इसे सकारात्मक परिवर्तन बताया और अधिकारियों की सराहना की। उपमुख्यमंत्री ने कहा अभी विकास कार्य लगातार जारी हैं और जल्द सभी समस्याओं का समाधान जनता के सामने होगा।

देर के बालाजी इलाके में जहां कभी कमर तक पानी भर जाता था और वहां पानी की निकासी होने से लोगों में खुरशी के लहर है। जब उपमुख्यमंत्री को मौके पर देखा तो स्थानीय मटकी बेचने वाली एक बुद्ध महिला ने आकर उपमुख्यमंत्री का

आभार जताते हुए कहा कि बारिश के दौरान यहां कमर तक पानी भर जाता था और फुटपाथ पर रहने हुई उनकी मटकिया बर्ब जाती थी जिससे उनके व्यापार को नुकसान होता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। उपमुख्यमंत्री ने भी उनके आभार का स्वागत करते हुए उन्हें गले लगा लिया।

स्थानीय नागरिकों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि लंबे समय बाद इस स्तर पर समाधान और जवाबदेही देखने को मिल रही है। उपमुख्यमंत्री ने भी भरोसा दिलाया कि जनता की समस्याओं का समाधान ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

- 1.65 करोड़ अति संवेदनशील जनसंख्या की होगी स्क्रीनिंग

धूमपान व शराब का सेवन करने वाले, प्रवासी श्रमिक, आदिवासी समुदाय, पूर्व टीबी रोगी, खनन व निर्माण स्थलों पर कार्यरत श्रमिक, जेलों व झुग्गी बस्तियों में रहने वाले नागरिक शामिल हैं। इन सभी संवेदनशील वर्गों की घर-घर जाकर स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि किसी भी संभावित टीबी रोगी की प्रारंभिक स्तर पर पहचान हो सके।

राज्य क्षय रोग अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोनी ने बताया कि इस अभियान में आशा कार्यकर्ता व स्वास्थ्य कर्मी घर-घर जाकर लक्षणों की पूछताछ करेंगे। यदि किसी व्यक्ति में दो सप्ताह से अधिक समय तक खांसी, लगातार बुखार, ज्वर, लक्षणों में गिरावट, या भूख न लगना जैसे लक्षण पाए जाते हैं, तो उन्हें निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर जांच के लिए भेजा जाएगा। टीबी की पुष्टि होने पर संबंधित व्यक्ति को सरकारी अस्पतालों में निशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जानकारी दी कि अभियान के दौरान टीबी संक्रमण की अधिक संभावना वाले समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इनमें एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति, डायबिटीज के रोगी, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग, कुपोषित व्यक्ति,

1 3 2 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, सहरौद का संचालन शुरू

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की किसानों को वर्ष 2027 से दिन में अच्छी गुणवत्ता की बिजली उपलब्ध करवाने के निर्देशों की पालना में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए विद्युत प्रसारण निगम ने बारां में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन, सहरोद का संचालन शुरू कर दिया गया है।

प्रसारण निगम के प्रबन्ध निदेशक सिद्धार्थ सिहाग ने बताया कि सहरोद के आस-पास के इलाको में बिजली सप्लाई में बार-बार टूटपिंग आती थी तथा वोल्टेज में उतार-चढ़ाव रहता था, इसी कारण सहरोद में 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही थी। सहरोद के 132 केवी ग्रिड सब-स्टेशन बनने से कुंजेद, सकतपुर, सहरोद, अरदान एवं आस-पास के क्षेत्रों में विद्युत छीजत में कमी आयेगी, वोल्टेज में सुधार होगा एवं निर्बाध विद्युत आपूर्ति होगी।

शेखावत ने ली गहलोत के बयान की चुटकी

जयपुर/जोधपुर । केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक

- केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बोले, दुकान का फीता तो कट गया, सामान नहीं बिका...

गहलोत के उस बयान पर चुटकी ली है, जिसमें उन्होंने दावा किया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने की साजिश चल रही है।

शेखावत ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और अशोक गहलोत का एक मीम शेयर करते हुए कहा कि दुकान का फीता तो कट गया, सामान नहीं बिका...।

मीम में अशोक गहलोत और राहुल गांधी को झूठ की दुकान का फीता काटते हुए दिखाया गया है।

- कुंजेद, सकतपुर, सहरोद, अरदान एवं आस-पास के क्षेत्रों को मिलेगी उच्च गुणवत्ता की बिजली
- ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में लगभग 26.44 लाख यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत छीजत की कमी संभावित है

सिहाग ने बताया कि इस ग्रिड सब-स्टेशन के बनने में 22 करोड़ रुपये की लागत आई है। इस ग्रिड सब-स्टेशन के निर्माण में लगभग 26.44 लाख यूनिट प्रतिवर्ष विद्युत छीजत की कमी संभावित है जिससे लगभग 2.2 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष राजस्व की बचत अपेक्षित है।

देवनानी फ्रांस एवं जर्मनी की सात दिवसीय यात्रा से आज लौटेंगे देवनानी का जयपुर में होगा भव्य स्वागत

- अध्ययन भ्रमण में देवनानी ने दोनों देशों के सांसदों, प्रवासी भारतीयों से की मुलाकात, ऐतिहासिक धरोहरों को भी देखा

इस दौरान उन्होंने जर्मनी तथा फ्रांस की लोकतांत्रिक संस्थाओं का अवलोकन किया और वरिष्ठ सांसदों, नीति-निर्माताओं तथा भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। देवनानी ने प्रवासी भारतीयों के सुझावों को सुना और उनके समाधान का भरोसा दिलाया।

इस यात्रा के दौरान देवनानी ने "इंडो-जर्मन फाउंडेशन", "वेदांत-गेसेलशाफ्ट", बर्लिन मेयर ऑफिस और स्टेट असंबली, निर्माणधीन गणेश

मंदिर सहित विभिन्न आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक धरोहरों का अवलोकन किया। जर्मनी और फ्रांस के राजदूतवास में प्रवासी भारतीयों द्वारा सम्मान समारोह और संवाद कार्यक्रमों में सहभागिता करते हुए भारतीय संस्कृति, लोकतंत्र एवं राजस्थान की समृद्ध परंपराओं को वैश्विक मंच पर गरिमा के साथ प्रस्तुत किया। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी आत्मवी संवाद कर उन्हें राजस्थान से जुड़ने एवं राज्य की विकास यात्रा में सहभागी बनने का आह्वान किया।

राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष की यह यात्रा न केवल एक संसदीय अध्ययन के रूप में उल्लेखनीय रही, बल्कि इसने भारत और यूरोपीय देशों के बीच लोकतांत्रिक सहयोग, सांस्कृतिक समरसता और पारस्परिक समझ को भी सुदृढ़ किया।

आवासन मंडल आयुक्त तलब, पालना नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी

- वर्ष 1980 में मानसरोवर आवास योजना में आवंटित प्लॉट का कब्जा पीड़ित को सौंपने के आदेश वर्ष 2016 में होने के बावजूद भी आज तक नहीं हुई पालना
- परिवादी ने दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों आयोग ने मंडल के आयुक्त सहित अन्य अधिकारी को जमानती वारंट से तलब किया

को कहा था, लेकिन आयुक्त की ओर से आदेश की पालना नहीं की गई। ऐसे में आयुक्त को 27 जून को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं।

गौरतलब है कि रमेश चन्द्र गुप्ता ने जनवरी, 1980 में मानसरोवर योजना में मध्यम आय वर्ग के आवास के लिए आवेदन किया था। परिवादी ने पता बदलने पर नए पते की सूचना भी आवासन मंडल को दी थी, लेकिन मंडल ने मकान का आरक्षण पत्र पुराने पते पर ही भेजा। जिससे वह तय अवधि में राशि जमा नहीं करा सका।

वहीं बाद में कई बार प्रार्थना करने पर भी उसे मकान का आवंटन नहीं किया। इस पर परिवादी ने साल 2013 में जिला उपभोक्ता आयोग में परिव्राद

पेश किया। जिस पर 3 मई, 2016 को फैसला देते हुए आयोग ने साल 2010 की दर से दो माह में आवास आवंटित करने को कहा और साथ ही आवासन मंडल पर 1.10 लाख रुपए का हर्जाना लगाया।

इस आदेश के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग तक अपील की गई, लेकिन आवासन मंडल को राहत नहीं मिली। दूसरी ओर परिवादी ने जिला आयोग में प्रार्थना पत्र पेश कर दोषी अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई करने की गुहार की। जिस पर सुनवाई करते हुए गत दिनों आयोग ने मंडल के आयुक्त सहित अन्य अधिकारी को जमानती वारंट से तलब किया। इस आदेश को आयुक्त ने हाईकोर्ट में चुनौती दी।

मोजाम्बिक में 1 2 0 0 दिव्यांगों को जयपुर फुट समेत कृत्रिम उपकरण लगेंगे

विद्याधर नगर में जेडीए की कार्रवाई के दौरान विवाद

जयपुर। विद्याधर नगर सेक्टर 8 में जेडीए की कार्रवाई के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। विवाद कियोस्क हटाने और अतिरिक्त पक्ष को लेकर शुरू हुआ। एक पक्ष का आरोप है कि गहलोत सरकार के दौरान जिन

- कियोस्क हटाने को लेकर दो पक्षों में झड़प
- पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया

कियोस्क का एलॉटमेंट किया गया था, उन पर दूसरे लोगों का कब्जा है। विरोध करने वाले पक्ष ने सांकेतिक धरना दिया। उनका कहना है कि रोड पर मीट की दुकान की वजह से यहां से गुजरने वाली महिलाओं को परेशानी होती है। वहीं दूसरे पक्ष का दावा है कि उन्होंने कोर्ट से स्टे ले रखा है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाइश कर मामले को शांत करवाया। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है।



विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्द्धन सिंह ने मोजाम्बिक की राजधानी मोपूतो में जयपुर फुट विकलांग पुनर्वास शिविर का उद्घाटन किया।

चलने फिरने योग्य बनाया गया। फ्लोरेन्सिया और दो अन्य मोजाम्बिक के तकनीशियनों को विशेष रूप से जयपुर फुट के निर्माण की विधि का प्रशिक्षण जयपुर के बी.एम.वी.एस.एस केन्द्र में दिया गया। मोपूतो में आयोजित उद्घाटन समारोह में मोजाम्बिक के स्वास्थ्य मंत्री बी.एम.वी.एस.एस के प्रशासनिक अधिकारी विष्णुकांत शर्मा ने जयपुर फुट की निर्माण विधि की जानकारी दी

यह शिविर 50 दिनों तक चलेगा। उपस्थित थे। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्द्धन सिंह ने कहा कि मोजाम्बिक की आजादी के पचास वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित इस शिविर से जहां 1200 विकलांगों को लाभ होगा वहीं भारत और मोजाम्बिक के बीच आपसी सद्भाव भी देगा। विदेश राज्य मंत्री मोजाम्बिक के स्वास्थ्य मंत्री को बी.एम.वी.एस.एस के प्रशासनिक अधिकारी विष्णुकांत शर्मा ने जयपुर फुट की निर्माण विधि की जानकारी दी

आदि विषयों पर समीक्षा कर रही थीं।

औद्योगिक विद्युत कनेक्शन के प्रकरणों की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऐसे मामलों में देरी का कारण पूछा। अभियंताओं ने आवेदक के स्तर पर लॉबिंग होना बताया। इस पर डिस्कॉम चेयरमैन ने पुष्टि के लिए तत्काल आवेदकों से मोबाइल फोन पर बात कर देरी का कारण पता करने के निर्देश अधिकारियों को दे

दिए, जिनमें आवेदन के करीब तीन माह बाद भी कनेक्शन जारी नहीं हो सके थे। बैठक के बीच से ही अभियंताओं ने आवेदकों को फोन कर अब तक कनेक्शन नहीं होने का कारण पूछा। इन मामलों में डिमांड नोट जमा नहीं कराने, विदेश यात्रा पर जाने जैसे आवेदक के स्तर पर विलंब के कारण सामने आए।

डोगरा ने कहा कि धरैलू एवं अघरेलू, किसी भी प्रकार के कनेक्शन में देरी का असर डिस्कॉम की छवि पर पड़ता है। ऐसे में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी

श्रेणियों में उपभोक्ताओं को यथाशीघ्र कनेक्शन मिले।

डिस्कॉम चेयरमैन ने इस दौरान अभियंताओं को 50 हजार से अधिक बकाया वाले उपभोक्ताओं से बकाया राजस्व वसूली, बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में बिजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने, ट्रिपिंग रोकने के लिए ग्रिड सब स्टेशनों एवं फीडरों की नियमित चेकिंग तथा उनमें लोड के अनुरूप सुधार के सभी उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

डिस्कॉम चेयरमैन ने विद्युत भवन में जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों के जोनल मुख्य अभियंताओं के साथ बैठक में निर्देश दिए कि विद्युत तंत्र में सुधार के लिए फील्ड विजिट बढ़ाएं। सुग्री डोगरा ने कहा कि प्रत्येक जोन में एफआरटी, हाई वोल्टेज वाले सब डिवीजन, जीएसएस, सॉलरआरसी पर दिए जाने वाले कार्यों तथा आरडीएसएस योजना के कार्यों की प्रगति एवं आवश्यक सुधार कार्यों का निरीक्षण करें।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा : भजनलाल

मुख्यमंत्री ने कहा, लोकतंत्र सेनानियों ने जेलों में यातनाएँ सहकर संविधान की रक्षा की



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आपातकाल लगने के 50 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित “भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय- संविधान हत्या दिवस-2025” कार्यक्रम का दीप जलाकर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक गोपाल शर्मा सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।

- मुख्यमंत्री शर्मा ने बुधवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, आपातकाल लगने के 50 साल पूरे होने पर आयोजित सम्मेलन “भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय-संविधान हत्या दिवस-2025” कार्यक्रम को संबोधित किया।**
- मुख्यमंत्री ने कहा, हमने राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान निधि को पुनः बहाल किया है, जिसके तहत लोकतंत्र सेनानियों को 20,000 रूपए मासिक पेंशन और 4 हजार रूपए की चिकित्सा सहायता दी जा रही है।**

कहा कि आज लोकतंत्र सेनानियों का सान्निध्य पाकर उन्हें अत्यंत हर्ष एवं गौरव की अनुभूति हो रही है। मुख्यमंत्री ने भावी पीढ़ी से सेनानियों से उनके

संघर्ष के संस्मरण सुनने और प्रेरणा लेने का आह्वान किया। राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने सत्ता बचाने के लिए

आपातकाल लागू कर लोकतंत्र की हत्या की, मौलिक अधिकारों का हनन किया, मौसा जैसा कानून लाया गया, जिसमें अनिश्चितकालीन गिरफ्तारी का प्रावधान रखा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों के संस्मरणों से संकलित ‘लोकतंत्र रक्षा की कहानी-सेनानियों की जुबानी’ पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने परिसर में आपातकाल के 50 वर्ष पर आयोजित प्रदर्शनों का अवलोकन किया।

समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, विधायक गोपाल शर्मा सहित, अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे।

धर्मशाला ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
ओर डायवर्ट हो गया, जिससे शेडों में आराम कर रहे मजदूर बह गए बड़े हुए ज्यादातर मजदूर श्रींगर के बताए जा रहे हैं। एक शव टिल्लू के पास और दूसरा नगुनी में मिला। नगुनी में गई एस्डीआरएफ टीम से अभी संपर्क नहीं हो सका है। स्थानीय लोगों ने जल विद्युत परियोजना पर पैड़ कटाई और मलबा डालने का आरोप लगाया, जिससे नाले का बहाव बदला।

‘हमारे परमाणु ठिकानों को बहुत नुकसान हुआ’

तेहरान, 25 जून। ईरान के आखिरकार कबूल कर लिया है कि अमेरिकी हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को बुरा नुकसान हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई की तरफ से बुधवार को इसकी पुष्टि की गई है। हालांकि उन्होंने इस बारे में विस्तार से जानकारी देने से इनकार कर दिया कि यह नुकसान कैसा है और किस हद का हुआ है। अमेरिका ने रविवार 22 जून को बी-2 बॉम्बर्स और बंकर बस्टर बर्मां की मदद से ईरान के परमाणु अड्डों की निशाना बनाया था।

नाबालिग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आरोप पत्र पेश किया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि घटना के दिन कॉलेज के बाहर उसे पूर्व परिचित अभियुक्त मिला था। वह उसे घर छोड़ने के नाम पर अपने साथ ले गया। रास्ते में अभियुक्त ने उसे नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाई और वह बेहोश हो गई। इसके बाद उसे जयपुर में होश आया। तब अभियुक्त उसे बस से पटना ले गया और बाद में भीपाल ले आया। जहां उसने करीब एक सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अदालत को बताया कि यहां से अभियुक्त उसे वापस जयपुर ले आया और मुहाना मंडी के पास किराए के कमरे में रखा और यहां भी अभियुक्त ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया।

वहीं 20 अक्टूबर पुलिस आकर उसे लग गई। दूसरी ओर अभियुक्त की ओर से कहा गया कि उसकी बहन की सगाई पीड़िता के भाई के साथ हुई थी और वह उसके घर आता-जाता था। इस दौरान उनके बीच प्रेम हो गया और पीड़िता ने अपने आप को वयस्क बताया था।

दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुमाने से दंडित किया है।

शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी

फ्लोरिडा, 25 जून। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला तीन अन्य चालक दल के सदस्य अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय समय के अनुसार, दोपहर 12 बजकर एक मिनट पर मिशन को लांच किया गया। नासा ने बताया कि गुरुवार शाम चार बजकर ३0 मिनट पर डॉकिंग की टाइमिंग है। इस मिशन का संचालन भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं। क्रू कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट पर एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सवार

- शुभांशु भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजकर एक मिनट पर अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुए थे।**

होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा कर रहा है। इस मिशन का नेतृत्व अमेरिका की कमांडर पैगी व्हिटसन कर रही हैं, जिसमें शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोज उज्जान्स्की-विस्नीव्स्की मिशन विशेषज्ञ हैं। फ्लोरिडा में नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्रियों ने उड़ान भरी। कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट पर लांच होने के बाद चालक दल एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर प्रक्रमा प्रयोगशाला की यात्रा करेगा। नासा ने एक बयान में कहा कि मिशन का डॉकिंग समय गुरुवार, 26 जून को भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 4.30 बजे है।

(प्रथम पृष्ठ का शेष)
आधे हो उत्साहपूर्वक समर्थन करते हैं—जबकि 88 प्रतिशत डेमोक्रेट और 60 प्रतिशत स्वतंत्र मतदाता इसका विरोध करते हैं। यह विभाजन ऐसे राष्ट्र को दर्शाता है जो नेतृत्व को लेकर असमंजस और संदेह से जूझ रहा है।

आम लोगों में गहरी चिंता है, 5८ प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि ये हमले अमेरिका के लिए और ईरान के खतरे को कम नहीं करेंगे बल्कि बढ़ा देंगे। यहां तक कि जो लोग हमलों का समर्थन करते हैं, उनमें से भी केवल 55 प्रतिशत ही मानते हैं कि इससे खतरा वास्तव में कम होगा। यानी बल प्रयोग का तर्क हमले समर्थकों की भी पूरी तरह से आपसवस्त नहीं कर पा रहा।

और भी अधिक चिंता की बात यह है कि केवल 32 प्रतिशत अमेरिकी मानते हैं कि अमेरिका ने हमले से पहले पर्याप्त कूटनीतिक प्रयास किए।

नयी दिल्ली, 25 जून। उच्चतम न्यायालय ने जमानत आदेश के बावजूद 28 दिनों तक एक व्यक्ति को जेल में रखने को स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करार देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को उस व्यक्ति को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है।

न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एन के सिंह की पीठ बुधवार को बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि गाजियाबाद जेल प्रशासन, 29 अप्रैल को पारित शीर्ष अदालत के आदेश और 27 मई के औपचारिक रिहाई आदेश के

लिखा, “जीवन यापन की लागत (खर्च) कामकाजी लोगों के लिए बहुत अधिक है, लेकिन जोहरान का मानना ​​है कि सरकार इस लागत को कम कर सकती है और हमारे शहर में जीवन को आसान बना सकती है, वे किराया कम करेंगे, निवृत्त स्त्रीय सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध कराने और परिवार पालने को आसान बनाने के लिए हर उपलब्ध साधन का उपयोग करेंगे।”

ममदानी ने वादा किया है कि वे मेयर बनने के बाद तुरंत सभी स्थिर किएपदारों के लिए किराया स्थिर कर देंगे और न्यूयॉर्क के बायियों को घर बनाने के लिए हर उपलब्ध संसाधन का उपयोग करेंगे और किराया कम करेंगे। फास्ट और मुफ्त बसों का वादा करते हुए, उन्होंने प्रचार में कहा कि वे मेयर बनने के बाद हर शहर की बस का किराया स्थायी रूप से समाप्त कर देंगे और उन्हें तेज गति देने के लिए प्राथमिकता लेन, बस क्यू जंप सिग्नल और डेडिकेटेड लोडिंग जॉन का निर्माण करेंगे, किंग्स डेबल जॉनिंग करने वाले लोगों से बचा जा सके।

ममदानी न्यूयॉर्क के 6 सप्ताह से लेकर 5 साल तक की उम्र के सभी बच्चों के लिए मुफ्त देखभाल व्यवस्था लागू करेंगे, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी परिवारों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली प्रोग्रामिंग हो।

जयपुर-अजमेर हाईवे पर मैथेनॉल से भरा टैंकर पलटा, ड्राइवर जिंदा जला

मोखमपुरा के पास एनएच48 पर हुए हादसे में टैंकर पलटते ही आग लग गई

- हाईवे पर चल रहे कई वाहन चालक अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भाग गए।**
- इस हादसे ने दिसंबर 2024 में हुई भांकरोटा दुर्घांतिका की भयावह यादें ताजा कर दीं, जब एलपीजी टैंकर में आग लगने से हुए हादसे 20 से ज्यादा लोग मारे गए थे व 35 से ज्यादा लोग सलुस गए थे।**

सूचना मिलते ही, एसडीएम बलबीर सिंह, तहसीलदार राधेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक दीपक खंडेलवाल सहित, अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया।

टैंकर में भरा मेथेनॉल हाईवे पर बिखर गया। आग फैलने के डर से टैंकर के करीब चल रही गाड़ियां हाईवे पर ही रुक गईं। हादसे के करीब आधा घंटे बाद तक हाईवे पर जाम लगा रहा।

स्थानीय लोगों ने बताया कि बुधवार सुबह जैसे ही हादसा हुआ, लोग अपने वाहनों को छोड़ कर खुतों की तरफ भागे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि वह जयपुर की तरफ जा रहा था। इसी दौरान दूक पलटा और आग का गोला बन गया। सभी लोग डर गए और कार से उतरकर पीछे की तरफ भागे। अन्य गाड़ी वालों ने भी कार रोकी और खुले स्थान की तरफ भागने लगे। गनीमत रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ।

जानकारी के अनुसार, हाईवे पर टैंकर पलटने के बाद आग लगते ही

अधिकांश अमेरिकावासी ईरान पर ...

अधिकांश अमेरिकी जनता यह सवाल कर रही है कि क्या बल प्रयोग वाकई में जरूरी था – और क्या शांति के किसी विकल्प पर गंभीरता से विचार किया गया था?

इस पूरे मुद्दे के मूल में टुंप के सैन्य निर्णयों पर बढ़ता अविश्वास है, 55 प्रतिशत उत्तरदाता कहते हैं कि उन्हें टुंप पर “बहुत कम” या “बिल्कुल भी” भरोसा नहीं है कि वे बल प्रयोग को लेकर सही निर्णय लेंगे। केवल 45 प्रतिशत उन्हें “मध्यम” या “बहुत अधिक” भरोसेमंद मानते हैं। डेमोक्रेट में यह अविश्वास अत्यधिक (88 प्रतिशत) है, और स्वतंत्र मतदाताओं में भी यह काफी गहरा (62 प्रतिशत) है।

अमेरिकी जनता अब राष्ट्रपति के युद्ध-संबंधी अधिकारों पर नियंत्रण की मांग करने लगे हैं। सर्वे में शामिल 65 प्रतिशत मानते हैं कि टुंप को आगे

किसी भी सैन्य कार्रवाई से पहले कांग्रेस से अनुमति लेनी चाहिए। यहां तक कि उनकी दूक पलटा में भी 39 प्रतिशत रिपब्लिकन इस बात से सहमत हैं।

उम्र इस राजनीतिक विभाजन में एक और परत जोड़ती है। अमेरिकी में 35 वर्ष से कम उम्र के अमेरिकी इन हमलों को लेकर सबसे अधिक संशय में हैं जहां 68 प्रतिशत विरोध में हैं वहीं 45 प्रतिशत का कहना है कि उन्हें टुंप के सैन्य निर्णयों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। युवा रिपब्लिकन समर्थकों में केवल 20 प्रतिशत ही इन हमलों का जोरदार समर्थन करते हैं, जबकि पुराने रिपब्लिकन में यह आंकड़ा 53 प्रतिशत है। रिपब्लिकन पार्टी के भीतर यह पीढ़ीगत अंतर आने वाले महीनों में असर डाल सकता है।

एक बात पर लगभग सर्वसम्मति है, वह यह है: अमेरिकी सैनिकों का जमीनी युद्ध में नहीं भेजना चाहिए।

‘ 28 दिन अवैध हिरासत में रखा, अब 5 लाख रु. का मुआवज़ा दे यूपी सरकार’

- सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार के उल्लंघन का दोषी करार दिया**

बावजूद आरोपी को रिहा करने में पूरी तरह से विफल रहा है।

पीठ ने कहा, भगवान जानता है कि ऐसे कितने लोग जेलों में सड़ रहे हैं।न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तकनीकी बातों पर जोर देते वाले जेल अधिकारियों के आचरण की निंदा की। उन्होंने गाजियाबाद के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को इसकी चुक के कारण व्यक्ति की रिहाई में 28 दिनों की देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का आदेश दिया।

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 की धारा तीन और पांच (आई) के तहत गिरफ्तार किया गया वह व्यक्ति 24 जून तक हिरासत में रहा। अधिकारियों ने सफाई दी कि जमानत आदेश में एक उप-धारा की चुक के कारण व्यक्ति की रिहाई नहीं हो पायी थी।

न्यायमूर्ति विश्वनाथन ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा,स्वतंत्रता एक

केवल 9 प्रतिशत लोग ईरान में जमीनी सैनिक भेजने का समर्थन करते हैं, वहीं, 35 से ज्यादा लोग बुरी तरह झुलस गए थे। बुधवार को जहां टैंकर पलटा, उस जगह की दूरी भांकरोटा से करीब 30 किलोमीटर है। स्थानीय लोगों का कहना है पिछले साल हुए हादसे के बाद भी प्रशासन ने कोई सबक नहीं सीखा है। कैमिकल या गैस से भरे टैंकर की सुरक्षा को लेकर कोई सख्ती नहीं हुई है।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध करते हैं। यहां तक कि हवाई हमलों के समर्थक भी पूर्ण सैन्य तैनाती का 2 गुना से अधिक अनुपात में विरोध करते हैं।

यह सर्वेक्षण ईरान की जवाबी कार्रवाई और टुंप द्वारा युद्धविरोधी घोषणा से पहले किया गया था, और यह राष्ट्र की उस समय की कच्ची भावनाओं को दर्शाता है।

अंत में, यह सर्वेक्षण एक स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। अमेरिकी जनता एक और मध्यम-वर्गी संकट से चिंतित हैं, जबकि 68 प्रतिशत इसका पूरी तरह विरोध